

संपादक की कलम से

रोकना होगा इजराइल– फिलिस्तीन युद्ध

लगभग पैने दो वर्षों से दुनिया रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के रुकने के कांडे से इंतजार कर ही रही है, वहीं उसके समाने एक और बड़ी लड़ाई आकार लेती हुई नजर आ रही है। फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास द्वारा शनिवार के तड़के केवल 20 मिनटों में इजराइल पर पांच हजार रॉकेट दाग दिये गये। इससे इजराइल व गाजा पट्टी में 500 लोगों के मरने की खबर है, जिनमें 26 इजराइली सैनिक हैं। दक्षिणी इजराइल के बिशेबांग नामक शहर में 750 इजराइली नागरिक घायल हुए हैं। अनेक बेहद गम्भीर है। इसका जवाब देते हुए इजराइल ने गाजा पट्टी के 17 फिलिस्तीनी मिलिट्री शिविरों और चार सेना मुख्यालयों पर बड़ा हमला बोल दिया। दक्षिणी लेबानान पर उसने बम बरसाए हैं। इससे करीब 200 फिलिस्तीनियों की मौत हुई तथा डेढ़ हजार से भी अधिक लोग घायल हुए हैं। इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि 'उनका देश युद्ध में शरीक हो गया है।' अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन आदि पश्चिमी देशों के साथ यूरोपियन यूनियन ने इजराइल का समर्थन किया है। दूसरी तरफ ईरान ने इसको इस हमले के लिये बधाई देते हुए उसे आश्वस्त किया है कि इजराइल के खिलाफ लड़ाई में वह फिलिस्तीन व यूरस्लाम की आजादी के लिये बधाई देते हुए उसे आश्वस्त किया है कि इजराइल के साथ देगा। अरब देशों के साथ इजराइल की लड़ाई का इतिहास तक उसका साथ देगा। अरब देशों के साथ इजराइल को स्वतंत्र देश बनने के भी पहले से। अनेक बार इजराइल अपने मुस्लिम बहुल 8 पड़ोसी मुल्कों से उलझता रहा है जिस दौरान इनके बीच कई जगे हो चुकी हैं। हालांकि 1978 के मध्य में तकालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर के निमंत्रण पर तब के इजराइली पीएम मेनाकेम बेगिन एवं एक युद्धरत देश मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादत के बीच कैंप डेविड में शांति समझौता हुआ था लेकिन अन्य देशों के साथ ऐसा कोई माहौल कभी नहीं बन पाया। इन देशों के साथ इजराइल के हुए अनेक छोटे-बड़े संघर्षों ने फिलिस्तीन को अपनी जमीन खोने पर मजबूर ही किया। जहां तक ताजा लड़ाई की बात है, तो इसके आसार इस साल के अप्रैल से बनें लगे थे जब इजराइली पुलिस ने अल अक्सा मस्जिद में ग्रेनेड फेंककर इसे अपवित्र किया था। इस धर्म स्थल पर दोनों (इजराइल-फिलिस्तीन) अपना हक जताते हैं। यहूदी इसकी पश्चिमी दीवार को यहूदी मन्दिर का अंतिम अवशेष मानते हैं तो वहीं फिलिस्तीनियों की मान्यता है कि यह अल बराक मस्जिद की दीवार है। उनके लिहाज से मक्का व मदीना के बाद यह मुस्लिमों के लिये सबसे पवित्र स्थान है। 1970 के दशक में एक समझौता हुआ था कि गैर मुस्लिम यहां आ सकते हैं परन्तु वे कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं कर सकेंगे। पिछले दिनों इसलिये विवाद भड़का क्योंकि यहां आकर कुछ यहूदियों ने पूजा करने की कोशिश की थी। हमास ने यह आक्रमण ऐसे दिन पर (शनिवार को) बोला जब यहूदियों का पवित्र त्यौहार सिमचैट टोरा मनाया जा रहा था। इजराइल इन दिनों अपने अंदरूनी विवादों में भी व्यस्त है। सरकार द्वारा न्यायपालिका के अधिकारों में कटौती करने वाले कदमों के खिलाफ वहां जन आंदोलन जारी है।

पांच राज्यों मध्य प्रदेश

छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उनकी तारीखों का भी ऐलान हो गया है, अब चुनावी बिगुल बज चुका है, राजनीतिक दल एवं उम्मीदावार मतदाताओं को रिझाने, लुभाने एवं अपने पक्ष में मतदान कराने के लिये तरह-तरह के दावपेंच चलायेंगे, इन लुभावनी छटाओं के बीच एक दिन के राजा यानी मतदाता को सतर्क एवं सावधान होकर अपने मत का उपयोग करना होगा। चुनाव मतदाताओं के हाथ में एकमात्र लिप्तिक बहुत ही कारगर संवैधानिक अधिकार होता है, जिसके सहारे वे जनप्रतिनिधियों का ही नहीं राष्ट्र का भविष्य निर्धारित-निर्मित करते हैं। इसलिये वक्त की नजाकत को देखते हुए मतदाता किसी प्रलोभन में न आये और देश-हित में सृजन करें। गरीब देश की टूटी सांसों को जीने की उम्मीद दें। भ्रष्टाचार में आकंठ लिप्त धर्मनियों में ईमानदारी एवं पारदर्शिता का संचार करें। इस वक्त सब-कुछ बाद में, पहले देश-हित की रक्षा और उसकी अस्मिता है, राष्ट्रीय एकता का लक्ष्य है। मतदाता इसी लक्ष्य से पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव को निर्णायक मोड़ दे सकेगा। मतदाता को जागरूक होकर चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाना में सहयोग करना होगा। भारतीय लोकतंत्र दुनिया का विशालतम लोकतंत्र है और समय के साथ परिपक्व भी हुआ है। बावजूद इसके लोकतंत्र अनेक विसंगतियों एवं विषमताओं का भी शिकार है। मुख्यतः चुनाव प्रक्रिया में अनेक छिद्र हैं, सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा छिद्र चुनावों की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता को लेकर है। खरीद-फरोख्त, नशा एवं मतदाताओं को लुभाने एवं आकर्षित करने का आरोप भी लोकतंत्र पर बड़े दाग हैं। चुनाव सुधारों की तरफ हम चाह कर भी बहुत तेजी से नहीं चल पा रहे हैं। चुनाव आयोग जैसी बड़ी और मजबूत संस्था की उपरिस्थिति के बाद भी चुनाव में धनबल, बाहूबल एवं सत्ताबल का प्रभाव कम होने के बजाए बढ़ता ही जा



रहा है। ये तीनों ही हमारे प्रजातंत्र के सामने सबसे बड़ा संकट है। इसलिये पांच राज्यों में राजनीतिक दलों और मतदाताओं की ही नहीं, चुनाव आयोग की भी परीक्षा होगी। मतदाता की बड़ी जिम्मेदारी का यह एक दिन नये भारत-सशक्त भारत को निर्मित करने का आधार है। लेकिन विडम्बना ही है कि मतदाता अपने अमूल्य वोट को चंद चांदी के टुकड़ों में बेच देता हो, सम्प्रदाय-जाति के उन्माद में योग्य-अयोग्य की पहचान हो खो देता हो, वह मतदाता भला योग्य उम्मीदवार को कैसे विधायी सदनों में भेज पाएंगा? नये-नये नेतृत्व उभर रहे हैं लेकिन सभी ने देश-सेवा के स्थान पर स्व-सेवा में ही एक सुख मान रखा है। आधुनिक युग में नैतिकता जितनी जरूरी मूल्य हो गई है उसके चरितार्थ होने की सम्भावनाओं को उतना ही कठिन कर दिया गया है। ऐसा लगता है मानो ऐसे तत्व पूरी तरह छा गए हैं। खाओ, पीओ, मौज करो।

सब कुछ हमारा है। हम ही सभी चीजों के मापदण्ड हैं एवं निर्णयक हैं। हमें लूटपाट करने का पूरा अधिकार है। हम समाज में, राष्ट्र में, संतुलन व संयम नहीं रहने देंगे। यहीं आधुनिक सभ्यता का घोषणा पत्र है, जिस पर लगता है कि हम सभी ने हस्ताक्षर किये हैं। भला इन स्थितियों के बीच पांच राज्यों के चुनावों में हमें वास्तविक जीत कैसे हासिल हो सकेगी? आखिर जीत तो हमेशा सत्य की ही होती है और सत्य इन तथाकथित राजनीतिक दलों एवं उनके दामी उम्मीदवारों के पास नहीं है। किसी लोकतंत्र और उनके नुमाइंदों को देखकर इसका भान किया जा सकता है कि वहाँ के नागरिक, पौजूदा शिथित में मतदाता, कितने समझदार और जिम्मेदार हैं। इसी समझदारी का परिचय मतदाताओं को देना है। आधार उनके पास है ही। उन्होंने शासन देखा है, माहाल भोगा है, नीति एवं नियमों की अनदेखी देखी है, अपने जनप्रतिनिधियों को

रखा भी है और विपक्षियों को करीब से नहा भी है। वे भलीभांति महसूस कर करते हैं कि संवेदनशीलता एवं राष्ट्रहित उमीद वे किन से कर सकते हैं, कौन नका खुद का, उनके परिवार, समाज और ज्य का भला करने वाला है, किसके हाथ शासन की बांगड़ेर सौंपकर वे निश्चिंत हो करते हैं। जैसाकि हम जानते हैं कि लोग अपेक्षा ही अच्छा देखने के लिए बेताब हैं, उनके सब का प्याला भर चुका है। लोकतंत्र पर दागदार बनानेवाले अपराध और अपराधियों की संख्या बढ़ रही है। जो कोई धर की चुनौती स्वीकार कर सामने आता है, उसे रास्ते से हटा दिया जाता है। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री स्वयं एक नया रास्ता नाने, लोकतंत्र को सुट्ट बनाने एवं चुनावी खामियों को दूर करने की ठानी है, उसलिये एक नया सूरज तो उदित होगा। किन यह नया सूरज उगाने में मतदाता ही अग्रभूत है। मतदाता को दूरगामी एवं

परिपक्व होना होगा, प्रशिक्षित होना होगा, तभी लोकतंत्र सुधृद हो पायेगा एवं चुनाव के महासंग्राम के नीर-क्षीर से सक्षम एवं ईमानदार जनप्रतिनिधि चुने जा सकेंगे। जबकि अनेक मतदाताओं को अपने हिताहित का ज्ञान नहीं है, इसलिये हित-साधक एवं जिम्मेदार जनप्रतिनिधि एवं दल का चुनाव नहीं कर पाते। मतदाता की यह गलती एवं गैर-जिम्मेदारी आजादी के अमृतकाल में विश्राम पाये, इसके लिये इन पांच राज्यों के चुनाव कसौटी के हैं। ये चुनाव इसलिये भी महत्वपूर्ण है कि इनको अगले लोकसभा चुनाव की पूर्वींठिका के तौर पर देखा जा रहा है। इन पांच प्रदेशों से लोकसभा में 83 एवं राज्यसभा में 34 सांसद चुनकर आते हैं, ऐसे में कोई भी राजनीतिक दल इन चुनावों को हल्के में नहीं ले सकता। इन चुनावों के नतीजे आम-चुनाव के लिये हवा बनाने-बिाड़ने का आधार होगे, इसलिये राष्ट्रीय पार्टियां अपने तरकश सजाने लगी हैं। लेकिन मतदाता इस सजावटी महौल में अपने विवेक एवं समझ को नये पंख एवं परिवेश दे, स्वतंत्र की जिम्मेदारी को महसूस करें। खुद के होने का भान कराये।

जान-बूझकर से तो कोई भी मतदाता गलती

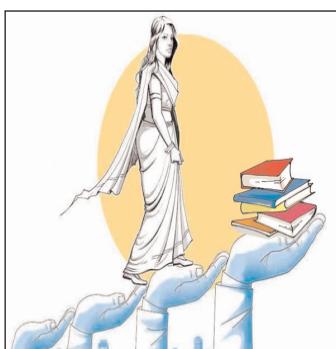
नहीं करता, पर बहकावे, प्रलोभन, जातपात, मोहमुस्थाता एवं अभाव में तो कभी-कभी अज्ञानतावश जनप्रतिनिधि चयन में उनसे गलती हो जाती है और गलत, अपराधी एवं अपरिकवच जनप्रतिनिधि चुन लिये जाते हैं। यह गलती न हो, इसके लिए उन्हें अच्छी तरह सोच-विचार कर फैसला करना चाहिए। ऐसा करते समय यह जरूर ध्यान रखना चाहिए कि फिर पांच साल उन्हें यह कहने का नैतिक हक नहीं रहेगा कि उनका जनप्रतिनिधि या सरकार अच्छा नहीं कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि और सरकार को कोसने वाले 35-40 प्रतिशत मतदाता हमारे बीच ऐसे भी हैं, जो मतदान ही नहीं करते। मतदान न करने की उनकी यह प्रवृत्ति भी लोकतंत्र की एक बड़ी विसंगति एवं कमजोरी का कारण है। पांच राज्यों की सरकारें चुनावों के चलते तमाम जनहित के फैसलों को टालती हैं या लोक-लुभावन फैसले लेती हैं।

मतदाता जागरूक बने एवं दिखाये अपनी ताक्त

6

विश्व दृष्टि दिवस प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को वैशिख स्तर पर मनाया जाता है। इस साल यह 12 अक्टूबर गुरुवार को पड़ रहा है। यह दिन दृष्टि हानि, अंधापन के साथ-साथ हृषि संबंधी समस्याएं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है, सभी लोगों के लिए अच्छी दृष्टि के महत्व पर प्रकाश डालता है। विश्व दृष्टि दिवस 2023 की थीम है हड्डाम पर अपनी आँखों से प्यार करें: कार्यस्थल में आँखों की देखभाल! यह विषय समग्र कल्याण के मूलभूत पहलू के रूप में कार्यस्थल में दृष्टि स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के महत्व को रेखांकित करता है, क्योंकि आधुनिक जीवनशैली एवं कार्यस्थलों पर कम्प्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बढ़ते प्रचलन में आँखें पर ही सर्वाधिक जोर पड़ती हैं। इस तरह जो लोग स्क्रीन पर बहुत अधिक समय बिताते हैं, उनमें समय के साथ आँखों से संबंधित कई तरह की बीमारियां होने का

खतरा रहता है। मोबाइल-कंप्यूटर या टेलीविजन की स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी आंखों के लिए बहुत हानिकारक होती है। विश्व दृष्टि दिवस नेत्र देखभाल सेवाओं तक समान पहुँच को बढ़ावा देता है, विशेष रूप से वर्चित और हाशिए पर रहने वाली आवादी के लिए। यह आंखों की देखभाल को किफायती और सभी के लिए उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर जोर देता है। विश्व दृष्टि दिवस इसलिये काफी महत्वपूर्ण है, दुनिया भर में नेत्र रोगों में बहुत अधिक बढ़ावा हो रहा है। दृष्टि हानि सभी उम्र के लोगों को प्रभावित करती है और अधिकांश प्रभावित लोग 50 वर्ष से अधिक आयु के हैं। बढ़ते नेत्र-रोगियों से दुनिया धुंधली हो रही है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार, एक अरब से अधिक लोग ऐसे हैं जो ठीक से देख नहीं सकते हैं क्योंकि उनके पास चश्मे तक पहुँच की सुविधा नहीं है। इनमें से एक अरब लोग निवारण किये जा सकने योग्य दृष्टि दोष से पीड़ित हैं। दृष्टि हीनता व्यक्तिगत गतिविधियाँ, घुमने-फिरने,



को कुछ हो जाए तो दुनिया कितनी बेरंग हो जायेगी? यह किसी के लिए भी गंभीर चिंता का विषय है, यह जीवन का अधूरपन है। आंखों का काम देखना और देखे हुए संदेश को मस्तिष्क तक पहुंचाना होता है। शरीर का सबसे ज्यादा कोमल अंग आंखें ही होती हैं, इसलिए जरूरी है कि हम अपनी आंखों का खास ख्याल रखें। आंखों को सही रखने के लिए सही खान-पान का होना बहुत जरूरी है।

आंखें शरीर का वह अंग हैं जो हमें

दूनिया की खूबसूरती का एहसास कराती हैं। हालांकि, समय के साथ जीवनशैली और खान-पान में गड़बड़ी के कारण इससे जुड़े खतरे बढ़ते जा रहे हैं। चाहे वह मोबाइल एवं कंप्यूटर पर बहुत अधिक समय बिताना हो या शुगर और बीपी जैसी बीमारियां हों, इन सभी का आंखों के स्वास्थ्य पर गलत प्रभाव पड़ रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका में अंधेपन और कमज़ोर नजर का मुख्य कारण मातियांविंद, डायबिटिक रेटिनोपैथी और ग्लूकोमा जैसी बीमारियों को बताया है। आँख या नेत्र जीवधारियों का वह अंग है जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील है। अच्छी दृष्टि किसी व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता पर गहरा प्रभाव डालती है। यह लोगों को दैनिक कार्य करने, शिक्षा प्राप्त करने और समाज में पूरी तरह से भाग लेने, समग्र कल्याण में पौरी योगदान करने में सक्षम बनाता है।

दृष्टि दिवस संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के साथ जुड़ा है, जिसमें इस बात पर जोर दिया जाता है कि अच्छी दृष्टि सुनिश्चित करना व्यापक

वैश्विक विकास उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक अभिन्न अंग है। विश्व दृष्टि दिवस वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देता है, दृष्टि हानि और अंधापन को रोकने के लिए एक साझा मिशन में व्यक्तियों और संगठनों को एकजुट करता है। हर साल दुनिया भर में अंधापन और दृष्टि हानि के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर लायंस क्लब फाउंडेशन सक्रिय हुआ, इसकी प्रेरणास्रोत बनी अमेरिकी लेखिका, शांतिकर्मी, युद्ध विरोधी राजनीतिक कार्यकर्ता, समाजसुधारक एवं प्रेरक उद्घोषक हेलेन केलर, वो स्वयं अंधी होने के बावजूद दुनिया में अनूठे एवं विलक्षण कर किये। 1925 में, जब लायंस इंटरनेशनल केवल सात वर्ष का था, प्रसिद्ध हेलेन केलर ने अपने वार्षिक सम्मेलन में लायंस सदस्यों से अंधता निवारण पर प्रेरक उद्घोषन देते हुए अधिरे के खिलाफ धर्मयुद्ध में अंधों के शूरवीर बनने के लिए चुनौती दी। उस भाषण ने लायंस की एक नई दिशा तय कर दी और तब से साइट फर्स्ट अभियान की नैत्र-क्रांति से अंधाता को दूर किया जा रहा है।

दुनिया भर में लाखों लायंस सदस्यों ने दृष्टिबाधित लोगों की मदद करने के लिए अपने उल्लेखनीय उपक्रम कर रहे हैं। इस प्रयास में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के साथ-साथ इंटरनेशनल एजेंसी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडेस (आईएपीबी) द्वारा सहयोग मिल रहा है। आईएपीबी एक वैश्विक संगठन है जिसमें 100 से अधिक देशों के विभिन्न धर्मार्थ संगठन और गैर सरकारी संगठन एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए मिलकर काम करते हैं जिसमें विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से अंधता रोकथाम और इलाज खोजने सहित अंधपन के मुद्दे पर जागरूकता फैलाई जाती है। दुनिया के कुछ हिस्सों में बहुत से लोगों को अधैरपन और अन्य ऑप्टिकल समस्याओं का खतरा अधिक है क्योंकि उनके पास आंखों की देखभाल तक पर्याप्त पहुंच नहीं है। विश्व दृष्टि दिवस एक चैरिटी में दान करने के लिए एक आदर्श प्रेरणा प्रदान करता है जो उन लोगों की मदद करता है जो अपनी आवश्यक दृष्टि देखभाल पाने के लिए

हड्डबड़ी में पार्टी की फजीहत करवाते भाजपा नेता

रमेश सर्वाफ धमोरा

ही मेरी फोटो पोस्टर से हटाकर माफी पोस्टर पर मेरी फोटो लगाई जाएगी। तिकाका साथा के साथे सेंट्रेटे

मानगना चाहए। पूर प्रदेश मे मरा फोटो लगे पोस्टर लगने से मेरी बहुत बदनामी हुई है। मेरे पास आज भी 188 बीघा जमीन है। मगर किसी का भी कोई कर्जा नहीं है। करीबन 70 वर्षीय माधुराम जयपाल जैसलमेर जिले के रामदेवरा क्षेत्र के रियिंगों की ढाणी के रहने वाले हैं। पोस्टर पर अपनी फोटो आने के बाद उन्होंने भाजपा के जिला स्तरीय नेताओं से संपर्क कर अपनी फोटो हटवाने के लिए बोल दिया है। इस बाबत जैसलमेर जिले के भाजपा अध्यक्ष चंद्र प्रकाश शरदा का कहना है कि सभी तरह के पोस्टर प्रदेश स्तर से बनवाए गए हैं। स्थानीय स्तर पर हमारी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं थी। एक किसान ने आकर बताया था। हम प्रदेश नेतृत्व को अवगत करवा देंगे। माधुराम का कहना है कि 2 महीने पहले दो लालड़के हमारे गांव में कैमरे लेकर आए थे। तब उन्होंने बोला था कि हम फसल खराबे की रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। सरकार के सामने आपके फसल खराबे की रिपोर्ट रखेंगे। तब उन्होंने मेरी फोटो ली थी। उगर किसान माधुराम के सबसे छिट बट जुगताराम का कहना है कि जब से मेरे पिताजी को पोस्टरों पर उनकी फोटो लगने के बारे में पता लगा है तब से वह बहुत टेंशन में रहने लगे हैं। मुझे बार-बार पूछते हैं कि वह फोटो हटी कि नहीं। मेरी बहुत बदनामी हो गई। मेरे पिताजी को बहुत तकलीफ हो रही है। हम लोग भाजपा के नेताओं से प्रार्थना करते हैं कि पोस्टरों से मेरे पिताजी की फोटो को हटवा दें। इस तरह की घटनाओं से राजनेताओं ने तो अपना स्वार्थ साध लिया है। मगर गांव में रहने वाले एक इज्जतदार किसान की इज्जत तो खराब हो गई जिसकी भाजपा कैसे भरपाई कर पाएगी। भाजपा नेताओं को चाहिए कि कोई भी कार्य करने से पहले उसे अच्छी तरह से जांच परख कर ही आगे बढ़ायें। जिस तरह की घटना एक गरीब किसान माधुराम के साथ घाटी है उस घटना को उसका परिवार जन्म-जन्मांतर तक नहीं भूला सकेगा। जिन पोस्टरों के बल पर भाजपा राजस्थान में सरकार बदलने के लिए हवा बन रही है। वह पोस्टर

सजाव ठाकुर

उसका हिंसात्मक विरोध करना दोनों अलग-अलग पहलू है। किसी विचार या मुद्दे से असहमत होने का मतलब हिंसा प्रतिफल के रूप में नहीं हो सकती है। विचारों से असहमति और विरोध का सबसे क्रूर और हिंसात्मक ताजा ताजा परिणाम फिलिस्तीन इजरायल युद्ध के रूप में सामने आया है जिसमें 2000 लोगों की जान चली गई और 5000 लोगों से ज्यादा धायल मानव शरीर कराह रहे हैं, दूसरी तरफ रूस युक्रेन युद्ध ने दोनों देशों के लाखों लोगों को बेघर कर दिया है और हजारों लोगों की जान चली गई है। आखिर मानवता को क्या हो गया है इंसान इंसान का इतना बड़ा दुश्मन कैसे बन गया है। लोग एक दृसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। वैशिक शर्ति में खलबली मच गई है। धरती विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है। ऐसे में भारत जैसे देश को भी सावधान और सतर्क हो जाना चाहिए। उसके परंपरागत शत्रु चीन और पाकिस्तान भी हमेशा भारत की सीमा में धात लगाए बैठे रहते हैं और आक्रमण का खतरा भी सदैव बना रहता है। आइये भारत पर एक रचनात्मक विश्लेषण करते हैं भारत विश्व का सबसे बड़ा

राष्ट्र हविचारक चितन, प्रलोकतंत्र के प्रमुख अवयव हराष्ट्र के किसी भी नीति में दृढ़ और असहमत होना एक स्वप्रक्रिया, प्रतिक्रिया हो सकती है और आम जनमानस का किसी पर आप सहमत होना र्थसामान्य बात हो सकती कि नहीं भी परिस्थितियों में असहमत हिंसा के रूप में कर्तव्य बद्ध योग्य नहीं होनी चाहिए, विरोध स्वरूप राष्ट्रीय संपत्ति की बबत किसी भी काल और खुल्ले स्वीकार्य नहीं है। यह राष्ट्र देश घातक और विकास की अवकाश को अवरुद्ध करने वाला आप कदम है। आंदोलन का स्वरूप शांति पूर्वक हो तो राष्ट्रीय आपजन के हित में ही आंदोलनकारियों को शायद गुमान नहीं है कि राष्ट्रीय संपत्ति आपके द्वारा दिए गए के रूप में रूपयों से ही निर्मित है, इसे नष्ट करके आप स्वयं संपत्ति का नुकसान ही कर आजादी के बाद से भारत के कई सामाजिक अर्थिक समस्याओं ने अर्थव्यवस्था उत्तरोत्तर प्रगति पर अवरोध किए हैं” देश की सामाजिक विषमताओं ने समाज में

आधारक प्रणाली पर जो भन्न में लगाम लगाई है। भारतीय में विषमता एवं विविधता भलिए एक बड़ी समस्या सामने खड़ी है। स्वतंत्रता तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के भारतीय समाज में विषमताएँ के लिए चुनौती बनकर बरत कई बाधाएँ उत्पन्न कर रही हैं, जातिगत संघर्ष बहुत हैं, जातिगत संघर्षों को राजनीति महत्वाकांक्षा ने बहुत बिल्कुल दिया है। राजनीति महत्वाकांक्षा के बल पर जो समीकरण को नए-नए रूप आयाम देती आई है और समाज में वर्ग विभेद आर्थिक कर के अपना उल्लंघनीयता मुख्य ध्येय बन चुका है। उसके तथा निम्न वर्ग सदैव सत्ता वेतन के लिए न सिफ्ऱ एक दूरी परस्पर विरोध करते हैं शासन प्रशासन के विरोध सदैव खड़े पाए गए हैं। सभी की लालसा में जातीय नक्सलवाद तेजी से समय पनपता जा रहा है। भारतीय में आज सिफ्ऱ जाती ही नहीं महत्वाकांक्षा देश के समाज समक्ष चुनौती बन गया है। १९५६ में हिंदू मुस्लिम जाति ऐतिहासिक तौर पर अपने

मास्त्रिय के ज़िंगड़ दश में अशात माहौल पैदा करने का एक बड़ा सबक बन चुके हैं। और यही वर्ग विभेद संघर्ष भारतीय आर्थिक विकास के बीच एक बड़ा अवरोध बनकर खड़ा है। पश्चिमी विद्वान भी कहते हैं कि भारत के राष्ट्र के रूप में विकसित होने में जाति एवं धर्म ही सबसे बड़ी बाधाएँ हैं जिन्हें दूर करना सर्वाधिक कठिन कार्य है क्योंकि इसकी जड़ें भारत के स्वतंत्रता के पूर्व से देश में गहराई लिए हुए हैं। जातीय वर्ग संघर्ष और भाषाई विवाद ऐसा मुद्दा रहा है जिससे लगभग एक शताब्दी तक भारत आक्रांत रहा है। आजादी के बाद से ही भाषा विवाद को लेकर कई आंदोलन हुए खासकर दक्षिण भारत राज्यों द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने एवं देश पर हिंदी थोपे जाने के विरोध में विरोध प्रदर्शनों को प्रोत्साहित किया गया। आज भी विभिन्न राज्यों में भाषाई विवाद एक ज्वलत एवं संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है, चाहे वह बंगल हो, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा और महाराष्ट्र में भी भाषाई विवाद अलग-अलग स्तर पर सतह पर पाए गए हैं।

समान सिविल संहिता को लेकर बहुसंख्यक संविधान में आक्रोश है दूसरी तरफ अल्पसंख्यक समुदाय

उसका अपना आमता एवं पहचान अस्तित्व हीन ना हो जाए। स्वतंत्रता के बाद से यह विकास की मूल धारणा थी कि पंचवर्षीय योजनाओं में वर्ग विहीन समाज में लोकतांत्रिक एवं धर्मनिरपेक्ष तरीके से समाज का आर्थिक विकास तथा रोजगार के साधन उपलब्ध हो सकेंगे। पर स्वतंत्रता के 75 साल के बाद भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में वर्ग विभेद भाषाई विवाद ने अभी भी आर्थिक विकास में कई बाधाएं उत्पन्न की हैं। सर्विधान में सदैव सकारात्मक वर्ग विभेद एवं विकास की अवधारणा को प्रमुखता से शामिल किया गया था और पंचवर्षीय योजनाओं में भी विकास को वर्ग विभेद से अलग रखकर विकास की अवधारणा को बलवती बनाया गया है। सामाजिक आर्थिक तथा धार्मिक विविधता वाले समाज को विवादों से परे रख आर्थिक विकास की परिकल्पना एक कठिन और दुष्कर अभियान जरूर है पर असंभव नहीं है।

इसी की परिकल्पना को लेकर आजादी के पश्चात से पंचवर्षीय योजनाओं का प्रादुर्भाव सरकार ने समय-समय पर लागू किया है। विकास की अवधारणा में राष्ट्र की मुख्य धारा में समाज के पिछड़े वर्ग को शामिल कर उन्हें सम्मुख लाना

